शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
472 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उच्च शिक्षा की प्रगति (1905–1921)उत्तर–पूर्वी प्रांत के संदर्भ में

ऐश्वर्य कीर्ति लक्ष्मी

एम0ए0, एम0एड0, शोध छात्रा,पाश्चात्य इतिहास विभाग,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: aishwarya15587@gmail.com

सारांश

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में लार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे–बंगाल विभाजन से भारतीय जनता रूश्ट हुई और इसका जमकर विरोध किया। तत्पश्चात् परिणाम स्वरूप बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ और धीरे–धीरे उसने स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की गयी, उसकी प्रमुख विषेशतायें थी–भारतीय षिक्षा के आदर्श, स्वदेश प्रेम की शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन, अंग्रेजी प्रभुत्व का अन्त तथा व्यवसायिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल। 1910 तक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोंलन के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक भारत वर्ष के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के स्तर पर की अनेक राष्ट्रीय संस्थाएं एवं विश्वविद्यालयों (उत्तर–पूर्वी प्रान्तों में) जैसे–जामिया मिलिया इस्लामियां, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय इत्यादि प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं की नींव पड़ी। इस अवधि में यद्यपि राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त विभिन्न सामान्य स्तरीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई, परन्तु संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि शिक्षा की प्रगति औपनिवेशिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप हुई।

प्रस्तावना

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही भारतवासियों के हृदय में स्वतंत्रता का अंकुर प्रस्फुटित हो गया था। सन् 1885 में ''भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस'' की स्थापना ने उसे राष्ट्रीयता की भावना को ओर गहरा कर दिया। सन् 1905 में ''बंगाल विभाजन'' ने उसके वास्तविक रूप को प्रदर्शित किया। उसी वर्ष कलकत्ता में होने वाले ''कॉग्रेस अधिवेशन'' में भारत की विदेशी सरकार के विरूद्ध स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वसम्मति से निश्चय किया। इस स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंम्भिक चार मुख्य अंग थेः–

1. 'स्वराज्य की मांग
2. स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग
3. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
4. राष्ट्रीय शिक्षा की माँग'[1]

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा की माँग

भारतीयलार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति से पहले से ही रूश्ट थे, अतः शिक्षा पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लग जाने से भारतीय जनता अत्यन्त क्रोधित हो गयी और साथ ही साथ शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन जोर पकड़ गया। '20 जुलाई 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसे सुनकर संपूर्ण बंगाल विभाजन का विरोध किया और जिसके बहिष्कार से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। बंग–भंग के शीघ्र बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा और राष्ट्रीय नेताओं ने ''राष्ट्रीय शिक्षा'' की मांग की। 1905 में काँग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पास किया ''समस्त देश में राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन किया जाये जो राष्ट्रीय लक्ष्य की प्रगति तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।'[2]

महात्मा गाँधी ने ''यंग इंडिया'' में अपने लेख प्रकाशित करके, भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर प्रहार किया। उन्होने इस शिक्षा के निम्नलिखित चार गंभीर दोष बताकर भारतीयों के लिये अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है।

1. 'यह शिक्षा अन्यायपूर्ण है।
2. यह शिक्षा, विदेशी संस्कृति पर आधारित है और इसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नही है।
3. इस शिक्षा का एक मात्र उद्देश्यः–मस्तिष्क का विकास करना है। इसमें हस्तकार्यों के लिये कोई स्थान नही है।
4. इस शिक्षा का माध्यम–अँग्रेजी है। अँग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती है।'[3]

श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भारतीय शिक्षा के अँग्रेजीकरण की निंदा और राष्ट्रीय शिक्षा की माँग करते हुये कहा कि ''राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक उत्तम उपाय और कोई नही हो सकता है कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का प्रमुख हो।''[4]

राष्ट्रीय शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत

राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि 'राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रधारा भी विचारों के अनुरूप होनी चाहिए, उस पर देश के प्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए। जिसके पीछे उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए।' अतः सामूहिक सहमति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा के निम्नलिखित आधार निर्धारित किये गये

1. **भारतीय नियंत्रणः–**काँग्रेस नेताओं के दृढ़विचार थे, कि 'शिक्षा व्यवस्था भारतीयों के हाथ में होनी चाहिये। सरकारी व्यवस्था में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन लाना संभव नहीं है।
2. **देशभक्ति को बढ़ावा देनाः–** काँग्रेस के नेताओं का विचार था कि 'शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र सेवा और देश भक्ति की भावनाओं का पोषण एवं संवर्द्धन हो।

3. **धार्मिक शिक्षा के निर्देश एवं प्राविधानः**—भारतीय संस्कृति में वृहद् प्रभाव को देखते हुये यह विचार किया कि 'राष्ट्रीय शिक्षा पद्धतियों में धार्मिक शिक्षा को आवश्यक रूप से दिया जाये।'
4. **पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की नकल न की जायेः**—राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधरों का यह विश्वास था कि 'शिक्षा सांस्कृतिक, बौद्धिक परंपराओं के अनुरूप देश में होनी चाहिये, न कि पश्चिमी व्यवस्था की नकल।
5. **आधुनिक भारत की आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम में शिक्षाः**— अँग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा के विचार को, जो कि सरकारी व्यवस्था में था, को एक बड़ी कमी के रूप में देखा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में यह दृढ़ विचार था कि 'शिक्षा भारतीय भाषाओं में प्रदान की जाये।'
6. **फीस में कमीः**—एक सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था हेतु यह विश्वास किया गया कि 'फीस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की पहुंच में होनी चाहिये और इसलिये जहाँ तक संभव हो, फीस कम से कम रखनी चाहिये।'[5]

उच्च शिक्षा की प्रगति (1905—1921)

सन् 1905—1921 के मध्य देश में विश्वविद्यालय स्तर तक अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई।

1. राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की प्रगति या निर्माण

(अ) प्रथम काल (1905—1911):—

नेशनल कॉउंसिल ऑफ एजूकेशन 1906

स्वदेशी आंदोलन बंग विभाजनक के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ। अतः इस परिषद की प्रवृत्ति आर्थिक थी, इसका प्रभाव सर्वांगीण रूप से जीवन के हर क्षेत्र में पड़ा 'स्वदेशी शिक्षा की मांग आगे बढ़ने लगी नेशनल कॉउंसिल ऑफ एजूकेशन के पीछे मूल कारण राष्ट्रीय जीवन को गति देना था, नेशनल कॉउंसिल को वर्ष 1906 में संगठित किया गया तथा एक्ट सं0 (21) वर्ष 1880 के अधीन प्रावधान के अनुरूप इसका पंजीकरण जून 1906 में किया गया, राष्ट्र शिक्षा मात्र बंगाल तक सीमित नही रही, इसका प्रचार भारत के अन्य भागों तक पहुंचा।'[6]

परिषद् के उद्देश्य

परिषद् का उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक विषयों की शिक्षा को राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप विशेषकर राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करना था, लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग हटकर था। परिषद् में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर लागू की जाने वाले निम्नलिखित तथ्यः—

1. 'शारीरिक व नैतिक शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाये तथा यह प्राविधान है कि धार्मिक शिक्षा जिससे कि जुड़ाव हो सके, उससे ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाय, जिससे उनमें देश—प्रेम तथा देश सेवा की इच्छा उत्पन्न हो।

2. ऐसे ज्ञान से सम्बद्धता की शिक्षा समाहित की जाये जिससे कि सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति के तथा पश्चिम के साथ–साथ साहित्य, इतिहास, दर्शन एवं देश के नाम के साथ शिक्षण व्यवस्था की जाये।
3. ऐसी शिक्षा प्रदान की जाये जो कि विज्ञान, रोजगारपरक तथा प्राविधिक शिक्षा हो, मुख्यतया उन विज्ञान कला और उत्पादक रखने की उस शाखा की ओर ज्ञान उत्पन्न करने वाली शिक्षा जिससे कि देश भौतिक संसाधन की आपूर्ति तथा इसकी बढ़ती हुयी मांग पूरी हो सके।
4. विज्ञान की शिक्षा में ऐसे वैज्ञानिक तथ्य समाहित किये जाये, देशी शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में विशेषकर ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जो कि आयुर्वेद व हकीमी दवाओं पर आधारित हों।
5. उच्च शिक्षा का स्तर समकक्षता के साथ स्थापित हो और उच्च स्तरीय अनुशासन लागू किया जाये, जिससे कि उचित ध्यान धार्मिक भावनओं तथा विभिन्न समाज के वर्गों के y ksd kpkj fu; e n'sk d h i jaj kv ksa d sv uq i 'kkfey gksA*7

देश के राष्ट्रीय नेताओं के राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा को व्यवहारिक रूप प्रदान के लिये गुरूदास बनर्जी की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय शिक्षा समिति'' की स्थापना की। 'इस समिति ने पश्चिम बंगाल में 11 और पूर्वी बंगाल में 40 राष्ट्रीय हाई स्कूलों का निर्माण किया। जिसमें मातृभाषा के माध्यम द्वारा उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त समिति ने पूना में विद्यालय तथा कलकत्ता में ''राष्ट्रीय कालेज'' की स्थापना की। इसके अलावा समिति ने कलकत्ता में एक ''टैक्निकल इंस्टीट्यूट'' को स्थापित किया। राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण में गुरूदास बनर्जी के अतिरिक्त रास बिहारी बोस तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1901 में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने ''शांति निकेतन'' (बोलपुर), में एक ''ब्रम्हचर्य आश्रम'' स्थापित किया जो आज ''विश्वभारती विश्वविद्यालय'' के रूप में विकसित दिखाई देता है। इसी समय के लगभग ''आर्य प्रतिनिधि सभा'' ने वृन्दावन और हरिद्वार में गुरूकुल स्थापित किये। ऐसा मानों नवनिर्मित राष्ट्रीय विद्यालय की प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का पुर्नरूत्थान अनिवार्य रूप से होगा परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन धीरे–धीरे शिथिल पड़ता गया और 1911 में बंगाल विभाजन के अंत के साथ यह भी समाप्त हो गया। कलकत्ता का ''नेशनल कालेज'' बंद हो गया और अन्य विद्यालय भी विलीन हो गये।'[8]

(ब) द्वितीय काल :–(1919–1921)

सन् 1919 में रोलेक्ट एक्ट एवं अमृतसर में जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड से क्षुब्ध होकर काँग्रेस ने महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में। अगस्त 1920 को सरकार के विरूद्ध ''असहयोग आंदोलन'' प्रारंभ कर दिया। सन् 1920 में गाँधी जी ने काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जनता द्वारा नवयुवकों से अपील की कि 'वे सरकारी विद्यालयों की स्थापना का प्रयास करें, फलस्परूप देश के विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कालेजों को त्यागर आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने उसके राष्ट्रीयकरण की माँग की किन्तु जब उन्हें

सफलता न मिली तो उनकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिये मौलाना मुहम्मद अली ने अलीगढ़ ने ''जामिया मिलिया इस्लामिया'' विश्वविद्यालय स्थापित किया (जिसे किन्ही प्रशासनिक कारणों के चलते 1925 में दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया)। अलीगढ़ का अनुकरण कर चार माह के अंदर देश के अन्य भागों में 'राष्ट्रीय स्कूलों एवं कालेजो जैसे–बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगला राष्ट्रीय विद्यालय आदि की स्थापना की गयी।' अतः '1916 में आचार्य कर्वे ने पूना में ''इण्डियन वीमेंस यूनवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे।'[9]

उच्च शिक्षा की प्रगति का दौर (1916–1921)
(उत्तर–पूर्वी प्रांत के संदर्भ में)

सन् 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 30 साल तक औपनिवेशिक भारत में कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नही हो सका। किंतु इस काल में कालेजों की संख्या बढ़कर 185 हो गयी। 'अतः इन कालेजों का पाँच विश्वविद्यालयों जैसे–कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पंजाब और इलाहाबाद द्वारा भार संभालना कठिन हो गया। परिणाम स्वरूप सन् 1913 में ''सरकारी–प्रस्ताव'' ने नवीन विश्वविद्यालयों ने भी इस संबंध में कार्य करने के लिये इच्छा व्यक्त की तथा इसके फलस्वरूप उत्तर–पूर्वी प्रांत में तीन नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी।'[10]

1. 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 1917
2. अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1920
3. लखनऊ विश्वविद्यालय, 1921

अतः उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के कार्य के लिये धन की पूर्ति सरकारी सहायता अनुदान एवं व्यक्तिगत साधनों की आर्थिक सहायता से होती थी। इन विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषतायें थीः–

1. ये आवासीय शैक्षणिक विश्वविद्यालय थे।
2. विश्वविद्यालय शिक्षण और संबद्धीकरण (एफीलेशन) के कार्य करते थे।'

कालेजों का विस्तार

सन् 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम में कालेजों को मान्यता प्रदान करने के लिये कठोर नियम बन जाने के कारण 1905 में कालेजों की संख्या 145 (1905 से घटकर 138 रह गयी। किन्तु छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने लगी।इस प्रकार 1921 के कालेजों की कुल संख्या 207 हो गयी जिसमें 54–443 छात्र पढ़ते थे।' परंतु इन कालेजों में व्यवसायिक शिक्षा के अभाव के कारण छात्रों को अध्ययन समाप्त करने के बाद बेकारी का सामना करना पड़ता था।[11]

उपसंहार

राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जिस उत्साह से प्रारंभ हुआ था, उस उत्साह से आगे नहीं बढ़ा। सन् 1911 में ''बंगाल विभाजन'' की समाप्ति के साथ, उसकी भी समाप्ति हो गई। फलस्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा की लगभग सभी संस्थायें अतीत की स्मृतियों के रूप में रह गई। किन्तु सन् 1920 में समय ने फिर करवट ली। मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से निराश होकर महात्मा गाँधी जी ने

अपना ''असहयोग आंदोलन'' पुनः प्रारंभ किया और उन्होने अपने देशवासियों को विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित किया। परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी प्रांतों में उनका निर्माण किया गया। उनमें उल्लेखनीय थीः—''जामिया मिलिया—इस्लामिया, बंगाल राष्ट्रीय विद्यालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ।'' महात्मा गाँधी के ''असहयोग आंदोलन'' ने फरवरी 1922 में चौरी—चौरा नामक स्थान पर हिंसात्मक रूपधारण किया। यह समाचार प्राप्त होने पर महात्मा गाँधी इतने अधिक व्यथित हुये कि उन्होने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह भी प्रायः लुप्त हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1. लिस्ट ऑफ द पेपर्स, ए0आई0सी0सी0 फस्ट इंस्टालमेन्ट फाइल नं0—1 रेजोल्यूशन पॉज्ड एट द कांग्रेस सेशन 1885—1920 (थ्री कॉपीज), तीनमूर्ति पुस्कालय, नई दिल्ली
2. सिंह, चंदर पाल ,*''ए सागा ऑफ क्वेस्ट फॉर अल्टर नेटिव ऑफ, कॉलोनियल एजूकेशन''*, ओरिजनलस, दिल्ली, 2012
3. दीक्षित, एस0एस0, *''नेशल्जिम एण्ड इण्डियन एजूकेशन''*, स्टर्लिंग पब्लिकेशनस प्राइवेट लि0, नई दिल्ली 1966
4. वकील, के0एस0 *''एजूकेशन इन इण्डिया'',* एलाइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1966
5. अबरार, डॉ0 राहत, *''सर सैय्यद अहमद खाँ और भारतीय नवजागरण''* प्रिया साहित्य सदन, दिल्ली, 2017
6. व्यास, के0सी0, *''द डेवेलपमेन्ट ऑफ नेशनल एजूकेशन इन इण्डिया''*, बोरा पब्लिकेशन एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, दिल्ली 1994
7. सिंह ठाकुर प्रसाद, *''स्वतंत्रता आंदोलन और बनारस''*, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1990
8. विद्यावाचस्पति, इन्द्र, *''भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास''*, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाषन, नई दिल्ली, 2016
9. बंद्योपाध्याय, शेखर, *''पलासी से विभाजन तक और उसके बाद''*, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैक स्वाज, दिल्ली, 2017
10. सिंह, परमेश्वर, *''इतिहास के आइने में आधुनिक भारत'',* इन्टेक्स प्रिंटर्स, लखनऊ, 2007
11. राय, सत्या एम0, *''भारत में राष्ट्रवाद तथा उपनिवेशवाद''*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2000
12. देसाई, ए0आर0, *''भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि'',* मैकमिलन, दिल्ली, 2007
13. सिंघल, डॉ0 महेन्द्र, *''भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें'',* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, जयपुर, 1971
14. अग्रवाल, जे0सी0, *''लैण्डमार्क ऑफ दि मॉर्डन एजूकेशन''*, विकास पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, 1984

15. त्रिपाठी, डा0 शालीग्राम, *''भारतीय शिक्षा का इतिहास'',* राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005

Footnotes

[1]व्यास, के0सी0, *''द डेवेलपमेन्ट ऑफ नेशनल एजूकेशन इन इण्डिया'',* बोरा पब्लिकेशन एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, दिल्ली 1994,पृ0–**80**

[2]लिस्ट ऑफ द पेपर्स, ए0आई0सी0सी0–1885–1920 फाइल नं0–1, रेजोल्यूशन पॉज्ड एट द इण्डिया नेशनल कॉग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता ऑन द 26, 27 दिसम्बर 1906, पृ0–132 (तीन मूर्तिपुस्तकालय, नई दिल्ली) पृ0–**132**

[3]व्यास, तदैव, पृ0–**80**

[4]पाठक, पी0डी0, *''भारतीय शिक्षा का इतिहास और उसकी समस्यायें''*, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2014, पृ0–**85**

[5]दीक्षित, एस0एस0, *''नेशल्जिम एण्ड इण्डियन एजूकेशन''*, स्टर्लिंग पब्लिकेशनस प्राइवेट लि0, नई दिल्ली 1966, पृ0.–**105**

[6]अग्रवाल, जे0सी0, *लैण्डमार्क ऑफ दि मॉर्डन एजूकेशन,* विकास पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, 1984, पृ0– 32

[7]अग्रवाल, वही, पृ0.–32

[8] त्रिपाठी, डा0 शालीग्राम, *''भारतीय शिक्षा का इतिहास'',* राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005, पृ0–**140**

[9] त्रिपाठी, वही, पृ0–**141**

[10] सिंघल, डॉ0 महेन्द्र, *''भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें'',* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, जयपुर, 1971, पृ0–**194**

[11] त्रिपाठी, तदैव, पृ0–**142**